डीईओ मुनीष चौधरी पर....

पेज एक का शेष

यह सब कुछ गौर से देख रही थी, लिहाजा शिकायतों का सिलसिला चल पड़ा। सर्व शिक्षा अभियान के चेयरमैन होने के नाते वर्ष 2007-8 में तत्कालीन अतिरिक्त जिला उपायुक्त संजय जून ने जांच का नाटक करके मुनीष को दोषमुक्त कर दिया। इतना ही नहीं उसके बाद से केस से सम्बन्धित बिलों आदि की फाइल भी लापता है। शिकायत करने वाले भला कब रूकने वाले थे, लिहाजा शिकायतों का सिलसिला लगातार चलता रहा।

मुनीष व उसके पति रिटायरर्ड एसई धर्म सिंह जो नगर निगम के घोटालों में काफ़ी चर्चित रहे हैं, ने हर जगह जांच अधिकारी को 'मैनेज' कर लिया। लेकिन वर्ष 2019 में शिक्षा विभाग के ही एक उच्चाधिकारी इनके द्वारा मैनेज नहीं हो पाये। उस अधिकारी ने साफ़-साफ़ लिखा बताते हैं कि या तो खर्च का हिसाब दो या रकम को वापस जमा कराओ। अब क्योंकि खर्च की फाइल तो नष्ट की जा चुकी है इसलिये अधिकारी ने मुनीष को दोषी ठहरा दिया। इसी को आधार मानकर माननीय अतिरिक्त सैशन जज ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

गौरतलब है कि मुनीष चौधरी की पूरी नौकरी इसी शहर की है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में इन्होंने ज्यादा समय 'बर्बाद' करने की अपेक्षा विभागीय दफ्तरों में अधिक बिताया है। ऐसी भी चर्चा है कि स्कूल की नौकरी के दौरान भी मुनीष महीनों-महीनों लगातार गैरहाजिर रहकर फर्जी हाजिरी भरवाती रही है। दफ्तर की नौकरी के दौरान भी ये साहिबा दफ्तर कम जाती रही हैं और दफ्तर खुद इनके घर पर अधिक आता रहा है। यानी कि डाक आदि लेकर सम्बन्धित बाबू लोग इनके घर से ही दस्तखत करा कर ले जाते रहें हैं।

बीते माह तिरंगा अभियान को लेकर इन्होंने जिला प्रशासन एवं हरियाणा सरकार की जो फजीहत कराई थी उसका कड़ा नोटिस लेते हुए तत्कालीन उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने इन्हें बूरी तरह से लताड़ते हुए रूल 7 के तहत इन्क्वायरी करने की बात कही थी। यह तो मुनीष की किस्मत जोड़ मार गई जो जितेन्द्र यादव का दबादला हो गया, वरना सबक तो वे भी इन्हें अच्छा-खासा सिखाने वाले थे।

मुनीष चौधरी का यह सारा खेल उसके व उसके पति धर्म सिंह के राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से घनिष्टता के बल पर ही चलता आया है। मुनीष चौधरी का सारा लेखा-जोखा, वर्षों से मीडिया में प्रकाशित हाते रहने के बावजूद, उक्त सम्बंध ही हैं जिनके बल पर, अयोग्य एवं भ्रष्ट होते हुए भी वह इस महत्वपूर्ण जिले की शिक्षा अधिकारी बन बैठी। जानकार बताते हैं कि ज़िले के भाजपाई विधायक राजेश नागर को छोड़कर शेष तीनों विधायक, एक केन्द्रीय मंत्री तथा खट्टर के कलेक्शन एजेंट अजय गौड़ के समर्थन से मुनीष इस पद पर तैनात हो पाई थी। अब देखना है कि ये ताकतें उक्त पुलिस जांच से मुनीष को कैसे और कब तक बचा पाती हैं?

डीसी से मिलने पहुंचे किसान, सौंपा ज्ञापन

करनाल। मांगों और समस्याओं को लेकर किसान जिला सचिवालय में डीसी से मिलने पहुंचे। इस दौरान किसानों ने डीसी सुशील सारवान से मुलाकत की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि वे काफी समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाए। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश महासचिव भूपेंद्र सिंह लाडी ने कहा कि तरावड़ी मंडी में पंखा लगाने की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है। आढ़तियों और किसानों की ओर से एक पंचायत की थी जिसमें इस समस्या को उठाया गया और सर्वसम्मति से इसका समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जैक वाली ट्राली से जो फसल अपने आप अनलोड हो जाती है उसकी मजदूरी किसान नहीं देगा। अपनी सबसे बडी समस्या को अवगत करवाते हुए किसानों ने बताया कि फसल पूरी तरह से पक चुकी है। मंडी में ढेर लगे हुए हैं।

सरकारी खरीद न होने से किसानों को अपनी फसल कम रेट पर राइस मिलरों को मजबूरी में बेचनी पड रही है। जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। एक तरफ रेट नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ तेला की बिमारी से फसल नष्ट हो रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द सरकारी रेट पर फसल को खरीदा जाए। हरियाणा सरकार इस समस्या पर गौर करे और जल्द से जल्द खरीद शुरू की जाए ताकि किसान को फसल का उचित मूल्य मिले। यदि सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देती तो किसानों को मजबूर होकर आंदोलन को तेज करना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि पिछले चार दिनों से किसानों ने तरावड़ी मंडी में धरना दिया हुआ था और मंडी के चारो गेटों पर ताला लगाकर अपनी समस्याओं को उठाया। तभी प्रशासन की नींद खुली।

इस अवसर पर लखविंद्र सिंह नौखरिया, रवि सरपंच पखाना, लखविंद्र सिंह सरपंच रमाणा, नछत्तर सिंह विर्क, चरणजीत गालबखेडी, प्रीतम गालबखेडी, मांगा सिंह सौंकडा, गुरविंद्र सिंह विर्क, मेजर सिंह वडैच, रणजीत सिंह, जोधबीर सिंह, निर्मल सिंह, बिल्लू रोड़ पडवाला, सुरेश पंडित, गुरनाम पाल, बाज सिंह नड़ाना सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।

मरीज़ रहित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते करीब चार साल से मोठूका गांव स्थित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार के कब्जे में है। इससे पहले इसका संचालन प्राइवेट हाथों में था। उस वक्त यहां करीब 1200-1500 मरीज ओपीडी में आते थे। करीब 100-150 मरीज़ वार्डों में भर्ती भी रहते थे। आपातकालीन सेवायें भी उपलब्ध थीं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर बीते करीब दो सालों से इसे चलाने की लोक-लुभावनी घोषणायें करते आ रहे हैं। अस्पताल तो आज तक भी चल नहीं पाया है लेकिन इससे क्षेत्र की जनता को होने वाले लाभ के स्वप्न जरूर दिखाये जा रहे हैं। लगभग यही काम बीते करीब 6 माह से संस्थान के डायरेक्टर डॉ. गौतम गोले कर रहे हैं। उन्होंने पूरे क्षेत्र में प्रोपेगेंडा करके ग्रामीणों को इलाज के लिये अपने यहां आमंत्रित किया। जो लोग इनके बहकावे में आ गये वे धक्के खाकर यहां से निराश लौट गये। संस्थान द्वारा उन्हें बीके अस्पताल जाने का रास्ता बताया गया जो वे पहले से ही जानते थे।

नियमानुसार किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के दाखिले केवल तभी किये जा सकते हैं जब 300 बेड के अस्पताल में कम से कम 180 मरीज़ दाखिल हों। इसी नियम के आधार पर शहर के सबसे बड़े एवं नव निर्मित मां अमृतमयी अस्पताल ने अभी तक कॉलेज शुरू करने के लिये आवेदन तक नहीं किया है। जाहिर है कि यह आवेदन तभी किया जायेगा जब ओपीडी व दाखिल मरीज़ों वाली शर्त पूरी हो जायेगी।

सरकार के उक्त संस्थान को इस आवश्यक शर्त से मुक्त करके चिकित्सा शिक्षा के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उस संस्थान में अभी तक न तो कोई आपातकालीन सेवायें हैं और न ही किसी भी प्रकार के मरीजों को देखने की कोई व्यवस्था है। दवाओं, शल्य चिकित्सा तथा एक्सरे आदि की तो बात करना ही फ़िज़ूल है। भरोसेमंद सूत्रों की माने तो इस संस्थान में बिजली पानी की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। दिन भर में तीन-चार घंटे बिजली का गायब रहना आम बात है। बीते सप्ताह तो बिजली का कोई खंभा टूट जाने से करीब दो दिन तक बिजली ठप्प रही। ऐसे में वहां तैनात डॉक्टर साहिबान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी के और भी कई कारण हैं। उन्हें न तो रहने के लिये आवास दिया जा रहा है और न ही आवास भत्ता। ग्रामीण क्षेत्र भत्ता जो खानपुर मेडिकल कॉलेज में 30 प्रतिशत तथा मेवात मेडिकल कॉलेज में 25 प्रतिशत मिलता है, यहां नहीं दिया जा रहा। और तो और पहली तारीख को मिलने वाला वेतन भी 10-15 तारीख तक मिल पाता है।

जानकार बताते हैं कि इन हालात के चलते यहां तैनात तमाम डॉक्टर अपने-अपने स्तर पर नई नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ लोग अम्मा के अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ यूपीएससी तथा अन्य माध्यमों से कहीं न कहीं और निकल भागने के प्रयास में जुटे हैं। यदि सरकार ने समय रहते इस ओर उचित ध्यान न दिया तो शीघ्र ही तमाम डॉक्टर भी यहां से पलायन कर जायेंगे।

बुजुर्गों की पेंशन काटकर उनको अपमानित कर रही है सरकार - दीपेंद्र हुड्डा

करनाल। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल में आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार बुजुर्गों की पेंशन काटकर उनको अपमानित कर रही है। हमारी सरकार आने पर जिन-जिन की पेंशन काटी गयी है उनको एक कलम से बहाल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को पेंशन न देनी पड़े इसलिये जिंदा लोगों को भी मरा हुआ बता रही है सरकार। अब तक लाखों बुजुर्गों की पेंशन बंद की जा चुकी है।

दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि आगे और भी बुजुर्गों की पेंशन बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। बुजुर्गों को पेंशन के लिए तरसाना सीधे तौर पर उनका अनादर करना है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेतहाशा महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन उनके बुढ़ापे का सहारा है। उनको पता चला है कि जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है वो बहुत कष्ट में बुढ़ापा काट रहे हैं। इस पर परिवार पहचान पत्र और बेवजह के आर्थिक मापदंडों को

थोपना गलत है।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के गांधरा (गांव) निवासी 102 वर्षीय बुजुर्ग दुलीचंद की पेंशन बंद करने की चर्चित खबर का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें कागजों में मृत घोषित कर उनकी पेंशन बंद कर दी। सरकार की इस कारस्तानी से आहत बुजुर्ग को खुद को जिंदा साबित करने के लिए रथयात्रा निकालनी पड़ी। दुलीचंद जी को अपनी पेंशन बनवाने के लिए पिछले करीब 6 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर पेंशन काटना सरासर गलत है।

उन्होंने प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पर बुजुर्गों के भरोसे को तोड़कर उनके साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को समर्थन दे रही जजपा ने बुजुर्गों से 5100 रुपये प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन तो भाजपा ने 3100 रुपये प्रति माह बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया था। लेकिन, दोनों ने मिलकर बुजुर्गों की भावनाओं को बुरी तरह से ठेस पहुंचायी है। प्रदेश के बुजुर्ग तो भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार से 5100 रुपये महीने की बुढ़ापा पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हर महीने 5100 रुपये पेंशन मिलना तो दूर जो पहले से मिल रही थी उसे भी तरह-तरह के बहाने बनाकर बंद किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गों के सम्मान भत्ते की कटौती और दूसरी तरफ उसके भुगतान में देरी इस कल्याणकारी योजना के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।

इस दौरान असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी, पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा, विधायक बलबीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडोला, पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, अनिल राणा, रणबीर संधू, त्रिलोचन सिंह समेत कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।